

रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एल०एम०/13-14/96.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार; 30 मार्च, 1996/ 10 चैत्र, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग  
(विधायी एवम् राजभाषा खण्ड)

अधिनूचना

शिमला-2, 4 अगस्त, 1995

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी०(16)-4/95.--हिमाचल प्रदेश रोड साईड लैण्ड कंट्रोल ऐक्ट, 1969 (1969 का 21) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख 29-7-1995 के

प्राधिकार के अधीन एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनु-  
पूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी)  
में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

हस्ताक्षरित,  
सचिव (विधि) ।

सचिव (विधि) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 30 मार्च 1996

## हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियन्त्रण अधिनियम, 1968

(1969 का 21)

(30-6-95 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित सड़कों के साथ-साथ और नियन्त्रित क्षेत्रों में अव्यवस्थित तथा निम्न-स्तर के विकास को रोकने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियन्त्रण अधिनियम, 1968 है। संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो ; परिभाषाएं।

(1) “कृषि” के अन्तर्गत बागवानी, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन और किसी बगीचे का वृक्षारोपण तथा अनुरक्षण है ;

(2) “इमारत” से कोई गृह, झोंपड़ी, छप्पर या अन्य छत वाली संरचना और उसका प्रत्येक भाग चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए हो या किसी भी सामग्री से निर्मित हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई दीवार या चिना हुआ मंच अथवा चिनी हुई खाई या निकास नाली भी है, किन्तु कृषि प्रयोजनों के लिए तम्बू या बाढ़ इसके अन्तर्गत नहीं है ;

(3) “कलक्टर” के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कलक्टर के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई प्राधिकारी है ;

(4) “पूजास्थल” के अन्तर्गत मन्दिर, गिरजाघर, मस्जिद, इमामबाड़ा, टनकिया, ईदगाह, समाधि, मठ और सती भी है ;

(5) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(6) “सड़क” से सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित सड़क अथवा सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इसके साथ-साथ सड़क बनाने की दृष्टि से सीमांकित मार्ग अभिप्रेत है ;

(7) “नियन्त्रित क्षेत्र” से धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(8) “वित्त आयुक्त” से हिमाचल प्रदेश का वित्त आयुक्त अभिप्रेत है और तत्समय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन वित्त आयुक्त की सभी या किन्हीं शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और पालन करने के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति इसके अन्तर्गत है ;

(9) “सरकार” या राज्य “सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(10) “अनुसूचित सड़क” से धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा इस रूप में घोषित सड़क अभिप्रेत है ; और

(11) “राजपत्र” से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

अनुसूचित  
सड़क और  
नियन्त्रित क्षेत्र  
की घोषणा।

3. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी लम्बाई या किसी सम्पूर्ण सड़क को "अधिसूचित सड़क" और ऐसी अनुसूचित सड़क के दोनों ओर की सड़क भूमि की ओर से पांच मीटर क्षेतिज दूरी तक यथा विहित क्षेत्र को, "नियन्त्रित क्षेत्र" घोषित कर सकेगी।

(2) सरकार, उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करने से कम से कम तीन मास पूर्व राजपत्र में और अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषा में मुद्रित कम से कम दो समाचार पत्रों में; यह कथन करते हुए कि ऐसी घोषणा करने का इसका प्रस्ताव है और उस भूमि की मोटे तौर पर सीमाएं विनिर्दिष्ट करते हुए जिसके बारे में ऐसी घोषणा करने का प्रस्ताव है अधिसूचना प्रकाशित करवाएगी और कलक्टर द्वारा ऐसी प्रत्येक घोषणा या उनके सार की प्रतियां अपने कार्यालय और उक्त सीमाओं के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे, ऐसी रिति में प्रकाशित की जाएगी जैसी वह उचित समझे।

(3) उप-धारा (1) में वर्णित सीमाओं में सम्मिलित किसी भूमि में हितबद्ध कोई अवरोध व्यक्ति कलक्टर द्वारा ऐसी अधिसूचना की प्रति प्रकाशित किए जाने की अन्तिम तारीख से 60 दिन के अवसान से पूर्व किसी भी समय, घोषणा करने या उक्त सीमाओं में उसकी भूमि अथवा उसके किसी भाग को सम्मिलित करने पर आक्षेप कर सकेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन प्रत्येक आक्षेप लिखित रूप में कलक्टर को किया जाएगा, और कलक्टर, इस प्रकार आक्षेप करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को या तो, व्यक्तिगत तौर पर या विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुने जाने के पश्चात् तथा ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जो वह उचित समझे, आक्षेपों पर अपनी सिफारिशों को अवर्णित करते हुए, रिपोर्ट सहित, उस द्वारा की गई कार्यवाहियों का अभिलेख सरकार को अग्रेषित करेगा।

(5) यदि, उप-धारा (3) द्वारा आक्षेप दायर करने के लिए अनुज्ञात समय के अवसान से पूर्व, कोई आक्षेप नहीं किया गया है, तो सरकार उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करने की तुरन्त कार्यवाही कर सकेगी। यदि ऐसा कोई आक्षेप किया गया है, तो सरकार उप-धारा (4) में निर्दिष्ट अभिलेख और रिपोर्ट पर विचार करेगी और या तो :—

(क) उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करने के प्रस्ताव का परित्याग कर सकेगी; या

(ख) उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमाओं में सम्मिलित सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग के बारे में ऐसी घोषणा कर सकेगी।

(6) उप-धारा (3) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा यदि वह भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 3 के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "हितबद्ध व्यक्ति" है या जहां भूमि, पूजा स्थल, समाधि, स्मारक, कब्रिस्तान, कब्र या मरघट स्थल द्वारा या के प्रयोजन के लिए अधिभोग में है वहां यदि वह उस धर्म का है जिसकी ऐसी इमारत है,

(7) उप-धारा (1) के अधीन की गई घोषणा, जब तक इसे प्रत्याहृत नहीं किया जाता है, इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह सड़क जिससे वह सम्बन्धित है, अनुसूचित सड़क है और वह क्षेत्र जिससे यह सम्बन्धित है, नियन्त्रित क्षेत्र है।

4. (1) कलक्टर, अपने कार्यालय में और ऐसे अन्य स्थानों पर जैसे वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुसूचित के रूप में घोषित सड़कों का संरक्षण दर्शाते हुए और उनके दोनों ओर पांच मीटर तक की भूमि को लागू होने वाले निबन्धनों की प्रकृति को उपवर्णित करते हुए योजनाएं निक्षिप्त करेगा।

अनुसूचित सड़कों की योजनाओं का कुछ कार्यालयों में निक्षिप्त किया जाना।

(2) इस प्रकार निक्षिप्त योजनाएं युक्तियुक्त समय पर जनता के निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी।

(3) इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा, योजनाओं के प्ररूप और विषय-वस्तु के बारे में और अनुमरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उसके आक्षेपों में सम्बन्धित किसी अन्य विषय की वाबत, उपबन्ध किया जा सकेगा।

(4) कलक्टर, किसी व्यक्ति को सहायकों या कर्मचारों सहित या रहित, किसी भूमि और इमारत पर या में जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण या तलमापन के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा: परन्तु सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के सिवाए, और ऐसी भूमि या इमारत के अधिभोगी या स्वामी को चौबीस घण्टे का नोटिस दिए बिना, प्रवेश नहीं किया जाएगा।

5. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, किसी नियंत्रित क्षेत्र में किसी इमारत का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण अथवा खुदाई या उसका विस्तार या सड़क तक पहुंच का साधन नहीं बनाएगा :

नियंत्रित क्षेत्र में इमारतों आदि पर निबन्धन।

परन्तु इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

- (क) उम इमारत की मुरम्मत को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व विद्यमान थी, या ऐसी इमारत के किसी परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण को जिसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन या परिवर्धन अन्तर्बलित नहीं है ; या
- (ख) किसी इमारत के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व विद्यमान थी और जिसमें कलक्टर की अनुज्ञा से कोई संरचनात्मक परिवर्तन या परिवर्धन अन्तर्बलित है ; या
- (ग) कलक्टर की अनुज्ञा से किसी सड़क तक पहुंच का साधन बनाने; या
- (घ) कलक्टर की अनुज्ञा से मोटर ईंधन भरण स्टेशन या बस-कतार आश्रय स्थान के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण को, या
- (ङ) कोई अन्य निर्माण जो कलक्टर की अनुज्ञा से विहित किया जाए।

6. (1) धारा 5 में निर्दिष्ट अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की वांछा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस इमारत, खुदाई, पहुंच साधन, मोटर ईंधन भरण स्टेशन या बस कतार आश्रय स्थान के बारे में जिससे आवेदन सम्बन्धित है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी सूचना से युक्त जैसी विहित की जाए, लिखित रूप में कलक्टर को आवेदन करेगा।

निर्माण आदि करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन और ऐसी अनुज्ञा देना या इन्कार करना।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा, या तो—

- (क) ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुज्ञा देगा, या
- (ख) ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार करेगा।

(3) जब कलक्टर, उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञा देगा या उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार करेगा तो अधिरोपित शर्तें या इन्कार करने के आधार ऐसे होंगे जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, युक्ति युक्त हों।

(4) कलक्टर एक रजिस्टर रखेगा जिसमें इस धारा के अधीन उस द्वारा दी गई सभी अनुज्ञाओं के बारे में पर्याप्त विशिष्टियां होंगी और यह रजिस्टर सभी हितबद्ध व्यक्तियों के निरोक्षण के लिए प्रभार रहित उपलब्ध होगा और ऐसे व्यक्ति उससे उद्धरण लेने के हकदार होंगे।

अपील का  
अधिकार।

7. (1) धारा 6 की उप-धारा, (2) के अधीन शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, वित्त आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(2) अपील पर वित्त आयुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

प्रतिकर।

8. (1) कोई भी व्यक्ति:—

- (क) उत्खात, निर्माण या उसका विस्तार करने की अनुज्ञा से इन्कार करने ब ऐसी अनुज्ञा से देने किन्तु मन्जूरी पर अधिरोपित करने; या
- (ख) सड़क तक पहुंच साधन बनाने की अनुज्ञा से इन्कार करने या ऐसी अनुज्ञा देने किन्तु मन्जूरी पर शर्तें अधिरोपित करने, या
- (ग) इमारत के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण की अनुज्ञा देने किन्तु मन्जूरी पर शर्तें अधिरोपित करने, या
- (घ) नियंत्रित क्षेत्र के लिए कोई अन्य अनुज्ञा देने किन्तु पर शर्तें अधिरोपित करने के; किसी आदेश से कारित या कारित हुई अभिकथित किसी क्षति, नुकसानी या हानि के प्रतिकर के लिए इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन, दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(2) जब इमारत को परिनिर्मित या पुनः परिनिर्मित करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने का आदेश कर दिया गया हो तो कोई व्यक्ति, जिसने धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा दिए गए अपील के अधिकार का प्रयोग कर लिया है, वित्त आयुक्त के आदेश की तारीख से तीन मास के अन्दर वित्त आयुक्त को इस आधार पर प्रतिकर के लिए उक्त आदेश द्वारा सम्बद्ध भूमि में उसके हित पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है, दावा कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन दावों की प्राप्ति पर वित्त आयुक्त या तो सम्बन्धित भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन अर्जित करने की कार्यवाही करेगा या दावे को उक्त अधिनियम के अधीन कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी को निपटारे के लिए अन्तरित करेगा:

परन्तु यदि वित्त आयुक्त भूमि को अर्जित करने का विनिश्चय करता है, तो —

- (i) किसी पूजा, समाधि, स्मारक, कब्रिस्तान, कन्न या मरघट स्थल की भूमि को इसमें सम्मिलित करना आवश्यक नहीं होगा, और
- (ii) दावेदार इस धारा के अधीन अपने प्रतिकर के दावे को तैयार और प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उस द्वारा उचित रूप से उपगत व्यय की रकम के अर्जक प्राधिकारी

द्वारा प्रतिसंदाय के लिए हकदार होगा और करार के व्यक्तिक्रम में ऐसी रकम का अवधारण, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कार्य-वाहियों में भूमि के मूल्य का विनिश्चय करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(4) इस धारा की कोई भी बात, दावे को पारस्परिक इकरार द्वारा तय करने से प्रवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

9. (i) जब धारा 8 के अधीन कोई दावा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी को निपटारे के लिए अन्तरित किया जाएगा, तो ऐसा अधिकारी दावेदार को संदेय प्रतिकर की रकम के अवधारण का, यदि कोई हो, अधिनिर्णय देगा।

प्रतिकर की रकम कैसे अवधारित की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम, किसी भी दशा में, उस पर इमारत, परिनिर्मित या पुनः परिनिर्मित करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने के, आदेश द्वारा इसके उपयोग और विकास पर वास्तविक रूप में अधिरोपित रूप में निर्बन्धनों को ध्यान में रखते हुए विद्यमान परिस्थितियों में भूमि के बाजार मूल्य तथा धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से ठीक पूर्व, जिसके अनुसरण में वह क्षेत्र जिसमें यह स्थित है। नियन्त्रित क्षेत्र घोषित किया गया है, बाजार मूल्य के बीच के अन्तर से, अधिक नहीं होगा और उप-धारा (1) के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा,—

(i) यदि दावेदार अधिनिर्णय करने वाले अधिकारी का समाधान नहीं कर देता है कि धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की तारीख के भूमि के विकास के प्रस्ताव तुरन्त साध्य हैं या ऐसे होते, यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता, अथवा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों द्वारा निवारित या हानिकारक रूप से प्रभावित न हुए होते, या

(ii) यदि और जहां तक भूमि किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन प्रवृद्ध वैसे ही निर्बन्धनों के सारभूत रूप से अधिधीन है जो उस तारीख को इस प्रकार प्रवृत्त थे जब इस अधिनियम के अधीन निर्बन्धन अधिरोपित किए गए थे, या

(iii) यदि दावेदार या दावेदार के किसी हित पूर्वाधिकारी को भूमि के बारे में इस अधिनियम के अधीन प्रवृत्त उन्हीं निर्बन्धनों या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन प्रवृत्त वैसे ही निर्बन्धनों के बारे में पहले ही प्रतिकर संदत्त कर दिया गया है।

(3) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के भाग iii, iv, v और viii के उपबन्ध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन किए गए अधिनिर्णय पर लागू होंगे मानो कि यह अधिनिर्णय उस अधिनियम के अधीन किया गया हो।

10. इस अधिनियम की कोई भी बात, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भूमि अर्जित करने या नियन्त्रित क्षेत्र में समाविष्ट भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बन्धन अधिरोपित करने, या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्भूत किसी दावे को पारस्परिक करार द्वारा तय करने की अनुज्ञा देने की सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अन्ध अधि-  
नियमितियों  
की व्यावृत्ति।

- 1 अनुक्षति के बिना किसी नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि को काठ कोयला भट्ठा, मिट्टी बर्तन भट्ठा या चूना भूमि का ईंट भट्ठा; पत्थर खदान या स्लेट खदान के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि का ईंट क्षेत्र या ईंट-भट्ठा के प्रयोजन के लिए उपयोग रूप में प्रयोग कलक्टर से अनुक्षति, जो प्रतिवर्ष नवीकरणीय होगी, के अधीन और उसकी शर्तों के का प्रतिषेध। अनुसार के सिवाय, नहीं किया जाएगा।

(2) सरकार ऐसी अनुज्ञप्ति देने और उसके नवीकरण के लिए भी ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगी और उसके बारे में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसी विहित की जायें।

(3) कोई भी व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्तिक के इन्कार से कारित या कारित हुई अभिकथित किसी क्षति, नुकसानी या हानि के लिए इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

अ  
अ।

अपराध और  
प्रां दण्ड।

12. कोई व्यक्ति जो,

(क) धारा 5 के उप-बन्धों के उल्लंघन में या धारा 6 अथवा धारा 7 के अधीन किसी आदेश द्वारा अधिरोपित किन्हीं शर्तों के उल्लंघन में किसी इमारत का परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण करेगा या कोई खुदाई अथवा उसका विस्तार करेगा या किसी सड़क तक पहुंच का साधन बनाएगा ;

(ख) धारा (ii) की उप-धारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमि का उपयोग करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उस द्वारा किया गया लगातार उल्लंघन साबित हो जाता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

2. उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलक्टर, किसी भी व्यक्ति को जिसने उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट उपबन्धों को भंग किया है, यथास्थिति; किसी इमारत या भूमि को, जिसके बारे में उक्त उप-धारा में यथावर्णित उल्लंघन किया गया है, इसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करने या उन शर्तों के अनुरूप, जिनका अतिक्रमण किया गया है, लाने का आदेश कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति यदि तीन मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहेगा तो स्वयं ऐसे उपाय कर सकेगा जो उसे आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे उपायों का खर्च यदि उससे मांग किए जाने पर संदत नहीं किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

कम्पनियों

13. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां कम्पनी और साथ ही ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, भी जो इस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :



परन्तु इस उप-धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाया अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

14. (1) कलक्टर या कलक्टर द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपराधों का प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, कार्यवाहियां सन्स्थित किए जाने के पश्चात् इस अधिनियम द्वारा शमन। या इसके अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन कर सकेगा।

(2) जहां अपराध का शमन किया गया है, वहां अपराधी को यदि वह अभिरक्षा में है; उन्मोचित कर दिया जाएगा और शमनित अपराध की वास्तव उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

15. (1) प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निरन्तर कोई न्यायालय इस अधि- अपराधों का नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं होगा। विचार विचारण और

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के लिए, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति पर, हिमाचल प्रदेश के किसी भाग में यथा प्रवृत्त उस धारा में विनिर्दिष्ट धन सम्बन्धि परिसीमा से अधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करना, विधिपूर्ण होगा। अपराधों का विचारण और जुर्माने के बारे में विशेष उपबन्ध।

16. (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने का आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी। विधिक कार्यवाहियों का वर्जन।

(2) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने को आशयित किसी बात से कारित नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के विरुद्ध न होगा।

17. इस अधिनियम की कोई बात,—

व्यावृत्ति।

(क) राजस्व अभिलेख में यथा दर्ज और सीमांकित किसी ग्राम के बसे हुए स्थल में सम्मिलित भूमि पर या किसी नगरपालिका, अधिसूचित या नगरीय क्षेत्र के स्थलों पर, इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से पहले ही निर्मित हैं। भवनों के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण;

- (ख) पूजा स्थल या समाधि, स्मारक, कब्र, कब्रिस्तान या मरघट अथवा पूजा स्थल, समाधि, स्मारक, कब्र, कब्रिस्तान या मरघट अथवा भूमि को परिवेष्टित करने वाली दीवार के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण अथवा भूमि जो सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना के प्रकाशन के ऐसे पूजा स्थल, समाधि, स्मारक, कब्र, कब्रिस्तान या मरघट द्वारा या ऐसे प्रयोजनों के लिए अधिकृत है,
- (ग) कृषि संकिय, भू-संरक्षण और पहाड़ी स्थिरीकरण के मामूली अनुक्रम में साधारण रूप से की गई खुदाई जिसके अन्तर्गत कुएं भी हैं, अथवा
- (घ) भूमि तक केवल कृषि प्रयोजनों के लिए पहुंचने के आशय से कच्ची सड़क के निर्माण ;
- को लागू नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

18. (1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) वह प्ररूप जिसमें धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन और योजनाएं दी जाएंगी और ऐसे आवेदनों में दी जाने वाली सूचना ;
- (ख) वे सिद्धांत जिनके अनुसार धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदनों को सामान्यतः कलक्टर द्वारा अनुज्ञात या अनुज्ञात किया जाएगा ;
- (ग) सड़कों तक पहुंच साधन बनाने के विनियमन ;
- (घ) धारा (11) के अधीन अनुज्ञप्तियों देने और नवीकृत करने के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस तथा ऐसी अनुज्ञप्तियां को विनियमित करने वाली शर्तें ;
- (ङ) वे सिद्धांत और शर्तें जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन मंजूर या इन्कार किए जाएंगे ;
- (च) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 6 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट रजिस्टर रखा जाएगा ;
- (छ) धारा 7 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; ऐसी अपीलों की बावत संदत्त की जाने वाली फीस और इनके साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज ;
- (ज) धारा 3 के प्रयोजन के लिए, किन्हीं निर्दिष्ट सड़कों की समतल दूरी ; और
- (झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्याधीन होंगे ।

(4) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे ।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।

19. किसी भी सिविल न्यायालय को, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों से सम्बन्धित प्रश्न को ग्रहण या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

20. प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू निरसन और दि यूनाईटेड प्रोविंसिस रोडसाईड लैंड कंट्रोल ऐक्ट, 1945 (1945 का 11) और पंजाब व्यावृत्तियां। पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि पंजाब शडयूल्ड रोड्स एण्ड कंट्रोल एरियाज से रैसट्रिक्शन आफ अनरेगुलेटेड डिवैल्पमेंट ऐक्ट, 1963 (1963 का 41) एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु उक्त अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई अथवा प्रारम्भ की गई या चालू रखी गई कोई कार्यवाहियां इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई या चालू रखी गई समझी जाएंगी।

